इसलिए सबकी रजामन्दी चाहिए। सिर्फ मेजॉरिटी, बहुमत से काम नहीं चलेगा। एक जमाना था, जब अल्पमत का, अकलियत का राज चलता था। चाहे राजा का राज हो, सरदारों का हो, रोम के नागरिकों का राज हो या क्षत्रिय जमात का राज हो। आखिर वह अल्पमत का ही राज्य था। उसका 'रीएक्शन', प्रतिक्रिया होकर अब मेजॉरिटी का, अक्सरियत का मायनॉरिटी पर, अकलियत पर राज चल रहा है। यह सर्कस चल रही है। कभी घोड़े पर कुत्ता खड़ा होता है तो कभी कुत्ते पर घोड़ा खड़ा होता है। हमें सोचना चाहिए कि आखिर मेजॉरिटी के राज्य के मानी क्या हैं? हम अपने नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं। ज्यादा लोग जिनको चुनते हैं, वे नुमाइंदे बनते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं. कि ज्यादा लोग ज्यादा अक्लवाले होते हैं या कम अक्लवाले? आपका तजुर्बा क्या है? ज्यादा लोग चुनेंगे याने मामूली अक्लवाले लोग ही चुने जायँगे। कोई असाधारण पुरुष नहीं चुना जायगा। क्या गुरु नानक आज होते तो चुने जाते, मिनिस्ट्री में लिये जाते, उनको कितने वोट मिलते? महाज्ञानी चुने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि महाज्ञानी को पहचानने के लिए भी अक्ल चाहिए, उतनी अक्ल मुहैया न हो तो औसत अक्लवाले लोग चुने जायँगे, जो डेयरी के दूध के जैसे होंगे। डेयरी का दूध एक अच्छी-से-अच्छी गाय के दूध की बराबरी नहीं करता है और खराब से खराब गाय के दूध की बराबरी भी नहीं करता है। इसी तरह आज के राज चलानेवाले लोग औसत अक्लवाले होते हैं। औसत अक्लवालों से सर्वोत्तम राज्य चलेगा, यह नामुमकिन है।

बहुमत नहीं, सर्वमत हो

साइन्स के जमाने में औसत अक्लवालों के हाथ में मिलिटरी रही तो बड़ा खतरा है। तुलसी रामायण में रामराज्य का वर्णन करते हुए कहा है, 'दंड जतिन कर' संन्यासियों के हाथ में दंड था। आज तो सिपाहियों की ३२ इंच की छाती देखकर उनके हाथ में दंडा दिया जाता है। इस दंडे से राज चलता है तो वह किस अक्ल का राज होगा? दंड-शक्ति अगर किसी के हाथ सौंपनी है तो औसत अक्लवाले आदमियों के हाथ में सौंपना गलत है। अगर सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के हाथ में सौंपी जाय तो दंड-शक्ति का कम-से-कम उपयोग होगा और जो उपयोग होगा, वह ठीक होगा। अब तो हिन्दुस्तान में यह चलता है कि इधर से पत्थर फेंके जाते हैं और उधर से गोलियाँ चलायी जाती हैं। कम्युनिस्टों से पूछा जाता है कि तुमने कम्युनिस्ट होकर भी केरल में गोली क्यों चलायी? वे जवाब देते हैं कि तुमने उधर जितनी गोलियाँ चलायीं, हमने उससे कम ही चलायीं। इसका माने यह हुआ कि कम गोली चलानेवाला बहादुर साबित होगा। गोली कतई नहीं चलनी चाहिए, ऐसी बात कोई नहीं करता। आज की लोकशाही की पद्धति में औसत लोग ही चुने जायँगे तो उसमें कम-से-कम इतना तो हो कि सबकी राय ली जाय। अगर ऊँचे लोगों का मार्ग-दर्शन नहीं मिल रहा है, औसत लोगों का ही मिल रहा है तो औसत में ५१ लोगों की ही राय क्यों लेते हो? सौ की क्यों नहीं लेते? महापुरुषों के हाथ में सत्ता देने में भलाई है, भगवान के हाथ में, स्थितप्रज्ञ के या महाज्ञानी के हाथ में सत्ता रहे तो हमारी भलाई होगी। माँ की गोद में हम सोते हैं तो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वह न हो और औसत अक्ल से राज चलाना पड़ता हो तो १०० की राय क्यों नहीं लेते हो, ५१ की ही क्यों लेते हो, इसका कोई उत्तर मुझे आज तक किसीने नहीं दिया। मुझसे पूछा जाता है कि या तो आप ५१ का राज पसन्द करो या ४९ का। दूसरा कोई चॉयस है ही नहीं।

मुझे पुराना किस्सा याद आता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब ने एक हिसाब रखा, जिसका उत्तर बीस लड़कों ने गलत लिखा और तीन लड़कों ने सही लिखा। इसलिए मास्टर साहब ने बीस लड़कों को नम्बर नहीं दिये, तीन को ही दिये। उन बीस में से एक लड़का खड़ा होकर बोला कि क्या हम बीसों गलत हैं और वे तीन ही सच्चे हैं? हम बीस एक बाजू हैं तो भी क्या गलत हैं? जहाँ मेजॉरिटी का राज चलता है, वहाँ इस प्रकार की हास्यास्पद बात चलती है। पुराने जमाने में मायनॉरिटी का राज चलता था और मेजॉरिटी की परवाह नहीं की जाती थी तो आज उसकी प्रतिक्रिया में मेजॉरिटी का राज चलता है और मायनॉरिटी की परवाह नहीं की जाती है।

मुख्य सत्ता अपने हाथ में रखें

हमें ऐसा तरीका ढूँढ़ना होगा, जिसमें राज्य के सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो और सबकी मिली-जुली राय से काम चले। इसके लिए जरूरी है कि सबका कोई मिला-जुला प्रोगाम बनाया जाय। क्या कम्युनिस्ट पार्टी, जन-संघ, पी० एस० पी०—सब मिलकर कोई कॉमन ग्राउण्ड नहीं हैं, सबका कॉमन प्रोग्राम नहीं बन सकता है? चुनाव में उनके जो मैनिफेस्टो निकले हैं, उनमें आप देखेंगे कि हर कोई कहेगा कि हमारे हाथ में राज्य आयेगा तो हम गुर्बत मिटायेंगे, राज्य-कारोबार का खर्च कम करेंगे। हर मैनिफेस्टो में आपको यही चीजें मिलेंगी। याने राम-नाम लिए बगैर किसीका नहीं चलता है, फिर चाहे वह होटल-कीपर हो या भजन-मंडली हो। फिर यह क्यों नहीं होता है कि सब के मैनिफेस्टो में जो कॉमन बातें हैं, उन्हींका एक कॉमन प्रोग्राम बनाकर उतना ही लेकर राज्य चलाया जाय और उसीपर जोर दिया जाय। ऐसा होगा, तभी हिन्दुस्तान में कुछ काम बनेगा और यह पिछड़ा हुआ देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो हर पाँच साल में फिर-फिर से अपना नसीब आजमाने की बात चलेगी तो यही होगा कि इधर प्लानिंग भी बढ़ रही है और उधर बेकारी भी। एक पंचसालाना योजना खत्म हुई, दूसरी खत्म हो रही है, तीसरी की तैयारी है, फिर भी बेकारी बढ़ ही रही है। इसलिए सर्वोदय का यह विचार है कि राज्य चलाने में सबके विचारों का समान अंश होना चाहिए और उसमें सबकी अक्ल इकट्ठा होनी चाहिए। इसके लिए हमें यह करना होगा कि गाँव-गाँव के लोगों को समझाना होगा कि आज जिस तरह तुम अपने नुमाइन्दों पर सभी मुख्य बातें सौंपते हो, वैसा मत करो। मुख्य बातें अपने हाथ में रखो और गौण बातें उनपर सौंपो।

एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि नुमाइन्दों का चुनाव बहुमत से नहीं बल्कि सर्वमत से हो। नुमाइन्दे सबके हों। अपूर्णों के सहयोग से पूर्ण बनाने की बजाय पूर्णों के सहयोग से परिपूर्ण बनाना लोकशाही का ही बेहतरीन तरीका है।

[चालू]

श्रीकृष्णदत्त भट्ट, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ द्वारा भार्गव भूषण प्रेस, वाराणसी में सम्पादित, मुद्रित और प्रकाशित।
पता : गोलघर, वाराणसी (उ० प्र०) फोन : १३९१ तार : 'सर्व-सेवा' वाराणसी
www.vinoba.in